



## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

---

शहरी चुनौती निधि को आकार देना:  
वितरण को सुदृढ़ करने के लिए कदम

---

[www.nextias.com](http://www.nextias.com)

## शहरी चुनौती निधि को आकार देना: वितरण को सुदृढ़ करने के लिए कदम

### संदर्भ

- भारत में लगभग एक तिहाई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, जिसके 2036 तक 40% हो जाने की संभावना है तथा 2050 तक 800 मिलियन से अधिक शहरी जनसंख्या हो जाने का अनुमान है, जो एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है।

### शहरी चुनौती का पैमाना

- विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार, भारत को 2036 तक अपनी शहरी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग ₹70 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी।
- हालाँकि, वर्तमान वार्षिक निवेश लगभग ₹1.3 लाख करोड़ है - जो प्रति वर्ष आवश्यक ₹4.6 लाख करोड़ का बमुश्किल एक चौथाई है। यह कमी निम्नलिखित कारणों से और भी जटिल हो जाती है:
  - स्थिर नगरीय वित्त, जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है;
  - शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में कर संग्रह की कम क्षमता;
  - स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT जैसी केंद्रीय योजनाओं का कम उपयोग;
- भारतीय शहरों की अप्रयुक्त क्षमता: 2011 और 2018 के बीच शहरी उपयोगिताओं के बुनियादी ढाँचे (रियल एस्टेट को छोड़कर) पर पूंजीगत व्यय औसतन सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.6% था।
- भारत की शहरीकरण चुनौती: 2027 की जनगणना से यह पता चलने की संभावना है कि भारत की 60% से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहेगी, जो 2011 में 31% थी।
  - केरल जैसे राज्य इस परिवर्तन का उदाहरण हैं, जहाँ संभावना है कि 2036 तक शहरीकरण दर 96% होगी।
- भारतीय शहरों के सामने अन्य चुनौतियाँ हैं अपर्याप्त स्थानिक नियोजन, जलवायु भेद्यता, सामाजिक असमानता और अलगाव, कमजोर शहरी शासन, तथा आर्थिक संकट से प्रेरित प्रवास।

### सरकारी प्रतिक्रिया: शहरी चुनौती निधि

- केंद्रीय बजट 2025-26 में इन मुद्दों के समाधान के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य है:
  - बैंक योग्य शहरी परियोजनाओं का 25% तक वित्तपोषण; शेष 75% बॉन्ड, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी से अपेक्षित।
  - विकास केंद्र के रूप में शहर, रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता जैसी पहलों को बढ़ावा देना;
- यह कोष प्रदर्शन-आधारित, प्रतिस्पर्धी शहरी विकास की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसका प्रारंभिक आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़ है।

### योजना सुधार और क्षमता निर्माण

- नीति आयोग चार क्षेत्रों - मुंबई, वाराणसी, सूरत और विशाखापत्तनम - में भूमि उपयोग और आर्थिक गतिविधि पर आधारित एक नए ढाँचे का संचालन कर रहा है। प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:
  - सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में योग्य शहरी योजनाकारों की बढ़ती माँग;
  - स्थायी विकास को दिशा देने के लिए स्थानिक नियोजन उपकरणों को अपनाना;

- स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और जवाबदेही में सुधार के लिए शहरी शासन की पुनर्कल्पना करना।
- भारत एक 'गतिशील मौन संकट' का जोखिम उठा रहा है, जहाँ इन सुधारों के बिना, अनियोजित शहरीकरण आर्थिक और सामाजिक प्रगति को कमजोर कर रहा है।

### नवाचारों का वित्तपोषण और वैश्विक साझेदारियाँ

- एशियाई विकास बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढाँचे, जिसमें मेट्रो विस्तार, आरआरटीएस कॉरिडोर और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं, को समर्थन देने के लिए पाँच वर्षों में 10 अरब डॉलर तक की राशि देने का वादा किया है। इसमें शामिल हैं:
  - संप्रभु ऋण और निजी क्षेत्र का वित्तपोषण;
  - परियोजना तैयारी के लिए तकनीकी सहायता;
  - रूफटॉप सौर ऊर्जा और पारगमन-उन्मुख विकास के लिए सहायता;
- एडीबी की भागीदारी शहरी समाधानों के विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और विशेषज्ञता के महत्व को रेखांकित करती है।

### शहरी चुनौती निधि को सुदृढ़ करने के लिए सिफारिशें

- **जीवनचक्र चिंतन को समाहित करें:** परियोजनाओं को संचालन, रखरखाव और नागरिक संतुष्टि को नियोजन में एकीकृत करना होगा, जिससे "उत्पाद के रूप में अवसंरचना" के प्रतिमान को "सेवा के रूप में अवसंरचना" में बदला जा सके।
- **निजी निवेश को जोखिम-मुक्त करें:** निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रथम-हानि गारंटी, ऋण संवर्द्धन और राजस्व कमी संरक्षण जैसे साधनों को यूसीएफ अनुदानों के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए।
- **संसाधन जुटाने के लिए शहरों को सशक्त बनाएँ:** शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को संपत्ति कर संग्रह का विस्तार करके और पारदर्शी उपयोगकर्ता-भुगतान शुल्क लागू करके वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार करना चाहिए। इसके बिना, निजी निवेशक अनिच्छुक रहेंगे।
- **संस्थागत क्षमता का निर्माण:** टियर 2 और टियर 3 शहरों को जटिल परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए समर्पित परियोजना तैयारी प्रकोष्ठों, तकनीकी मार्गदर्शन और सुव्यवस्थित अनुमोदनों की आवश्यकता है।
- **नवाचार को प्रोत्साहित करें:** यूसीएफ को स्केलेबल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए परिणाम-संबद्ध वित्त पोषण के साथ लक्षित चुनौती विंडो (जैसे, जल-सुरक्षित या शून्य-अपशिष्ट शहर) शुरू करनी चाहिए।
- **उच्च-प्रभाव परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें:** स्पष्ट राजस्व मॉडल वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसे अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, स्मार्ट जल प्रणालियाँ और पारगमन-उन्मुख विकास केंद्र, तथा साथ ही मौजूदा योजनाओं के साथ ओवरलैप से बचना चाहिए।
- **संस्थागत स्पष्टता सुनिश्चित करें:** एक सुव्यवस्थित, चुस्त शासी निकाय को यूसीएफ की देखरेख करनी चाहिए, ताकि चयन से लेकर निगरानी तक, हर चरण में स्वायत्तता, प्रतिस्पर्धा और नवाचार सुनिश्चित हो सके।

### विकसित भारत 2047 की ओर

- भारत को 2047 तक अपने विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए, अपने शहरों को विश्वसनीय, रहने योग्य और लचीला बनाना होगा। शहरी चुनौती निधि शहरी विकास को नया रूप देने के लिए एक सामयिक और उत्प्रेरक अवसर प्रस्तुत करती है।

- यदि इसे प्रभावी ढंग से डिज़ाइन और कार्यान्वित किया जाए, तो यह भारत के शहरी भविष्य की पूर्ण क्षमता को उजागर करने के लिए आवश्यक परिवर्तन को गति प्रदान कर सकता है।

Source: BS

#### दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न:** शहरी चुनौती निधि के पीछे की रणनीतिक दृष्टि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका डिज़ाइन और कार्यान्वयन भारत में शहरी शासन एवं बुनियादी ढाँचे की डिलीवरी को कैसे नया रूप दे सकता है?

